आवास योजना है । इस योजना के अंतर्गत राज्य एजेंसियों को निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर कुल निर्माण एवं सेवा लागत नियत सीमा और मानकों के अनुसार समुचित किस्तों में अनुदान के रूप में दी जाती है । 1992 से प्रभावी संशोधित लागत अधिकतम सीमा इस प्रकार है :—

(i) मकान निर्माण —8000 रुपए (9800 रुपए दुर्लभ क्षेत्रों में)

(ii) स्वच्छ शौचालयों और धुआं रहित चूल्हों का निर्माण—1400 रुपए

(iii) मूलभूत और जन सुविधाओं का प्रावधान—3300रु०

(ग) उत्तर प्रदेश बात अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

आश्रय सुधार

वर्ष	हुडको ऋण आवंटन	स्वीकृत केन्द्रीय सबसीडी	इन्दिरा आवास योजना
89–90 . . .	1801.73	480.46	3102.37
90–91 . . .	1884.38	504.50	2487.25
91–92 . . .	1720.58	215.50	2487.25

(घ) आश्रय सुधार योजना के अंतर्गत 1992–93 के दौरान 1,45,202 मकानों के सुधार के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव हैं । इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 1992–93 का लक्ष्य 18448 मकान है ।

उत्तर प्रदेश के छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के लिए एकीकृत योजना

1750. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991–92 के दौरान किसी भी छोटे और मध्यम दर्जे के शहर का चयन नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश के उन शहरों के क्षेत्र वार नाम क्या क्या हैं जिनका चयन किये जाने की सिफारिश की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :(क) और (ग) वित्त वर्ष 1991–92 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित कस्बों का चयन किया गया था जिनमें से प्रथम छ कस्बों तथा मुज्जफरनगर (एन सी यू कस्बा) को छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना (आई डी एस एम टी) के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा केन्द्रीय सहायता रिलीज कर दी गई है :

कस्बा	जिला
1. कोसीकलां	मथुरा
2. सिकंदराबाद	बुलन्दशहर
3. विलासपुर	रामपुर

कस्बा	जिला
4. मउरानीपुर	झांसी
5. चूनर	मिर्जापुर
6. मुवाना	मेरठ
7. देवबंद	सहारनपुर

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न हा नहीं उठता है ।

Acquisition of Estate belonging to Dr. Roerich and Devika Rani

1751. DR. ABRAR AHMED: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Central Government have received any proposal from Karnataka Government for its clearance to acquire the entire estate belonging to Dr. Roerich and Devika Rani; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Ministry of Urban Development has not received any such proposal from Government of Karnataka.

(b) Does not arise.

Ambedkar Awas Yojana

1752. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that amount deposited with DDA by some SC|ST applicants under Ambedkar Awas Yajana is being returned without interest, whereas interest was to be paid after one year of the date of deposit, if so, the reasons therefor;

(b) whether DDA propose to register and give priority number to all SC,ST applicants after 20,000 extending the scope of Yojana;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether the work of construction of flats would be got done by DDA through, private contractors specially under Ambedkar Awas Yojana, if so, what are the reasons for which work is being entrusted to contractors specially in the case of SCs|STs and for the rest DDA itself is going to construct the flats?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) DDA has reported that the amount deposited by unsuccessful applicants under Janta and LIG categories has been refunded without interest as there was no such commitment by the DDA.

(b) and (c) No, Sir, Ambedkar Awas Yojana was opened for registration of 20,000 applicants only.

(d) Work of construction of all flats is done through contractors. It is not proposed to follow a different procedure in case of flats under Ambedkar Awas Yojana.

बसंत विहार, दिल्ली में पार्कों पर अवैध कब्जा

1753. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 1991 के "नवभारत टाइम्स" में "वसंत विहार में पार्क में अवैध कब्जे' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में कितनी सफलता मिली है ?